



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 27 दिसम्बर, 2000/6 पौष, 1922

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171000, 26 दिसम्बर, 2000

संख्या पी०सी०एच०एच०एच०(1) 12/2000—हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2000 का प्रारूप, आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित करने के लिए, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 186 के उपबन्धों के अन्तर्गत, परन्तु ही सम्पत्तिका अधिसूचना द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 10 दिसम्बर, 2000 को प्रकाशित किया गया था ;

और नियत अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 4) की धारा 186 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या पी०सी०एच०एच०एच०(3)-6/94, तारीख 7 फरवरी, 1995 द्वारा अधिसूचित और 8 फरवरी, 1995 को राजपत्र (असाधारण) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं ; अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2000 है ।

2. नियम 85 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “उक्त नियम” कहा जाएगा),—

(क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के उप-नियम (1) में “और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम (1-क) जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“(1-क) सम्बन्धित उपायुक्त या उप द्वारा, विकास खण्ड अधिकारी के सिवाये, प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, यथाशक्य सम्भव परन्तु उप-नियम(1) के अधीन शपथ या राज्य निष्ठा का प्रतिज्ञान दिलाए जाने या किए जाने के सात दिनों के अपश्चात्, अपनी अध्यक्षता में, सभी निर्वाचित सदस्यों की, उनमें से किसी एक को पंचायत समिति का अध्यक्ष और दूसरे किसी को उपाध्यक्ष चुनने के लिए एक बैठक बुलाएगा :

परन्तु यह कि राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस उप-नियम के अधीन पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचन के परिणाम की घोषणा से एक सप्ताह के पश्चात् परन्तु एक महीने के अपश्चात् अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन बैठक करने की अनुमति प्रदान कर सकेगी :—

- (i) यदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण सात दिनों के भीतर बैठक बुलाई जानी सम्भव नहीं है ;
- (ii) यदि विधि और व्यवस्था की गम्भीर समस्या के कारण सात दिनों के भीतर बैठक बुलाना सम्भव या वांछनीय नहीं है ; और
- (iii) यदि विद्यमान पंचायतों की कालावधि के अवसान से 15 दिनों से अधिक शेषवधि से पूर्व निर्वाचन परिणाम घोषित कर दिए गए हैं ।” ; और

(ग) उप-नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा ; अर्थात् :—

“(5) उप-नियम (1) के अधीन शपथ या राज्य निष्ठा के प्रतिज्ञान के प्रयोजनों के लिए बुलाई गई बैठक के लिए कोई गणपूर्ति अपेक्षित नहीं होगी । उप-नियम (1-क) के अधीन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के प्रयोजनों हेतु बैठकों के लिए गणपूर्ति कुल निर्वाचित सदस्यों के दो तिहाई से होगी :

परन्तु यह कि यदि इस नियम के अधीन बुलाई गई प्रथम बैठक में गणपूर्ति के अभाव में, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन नहीं होता है, तो प्रथम बैठक की तारीख से दस दिन के भीतर द्वितीय बैठक बुलाई जा सकेगी और यदि फिर भी गणपूर्ति पूरी न होने पर द्वितीय बैठक भी स्थगित हो जाती है, तो तृतीय बैठक, द्वितीय बैठक की तारीख से दस दिन के भीतर बुलाई जा सकेगी । यदि तृतीय बैठक भी गणपूर्ति के अभाव में स्थगित हो जाती है, तो तृतीय बैठक के दस दिन के भीतर चतुर्थ बैठक बुलाई जा सकेगी और अधिनियम की धारा 131 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन साथ-साथ कार्रवाई की जाएगी । चतुर्थ बैठक के लिए गणपूर्ति कुल निर्वाचित सदस्यों के आधे से होगी ” ।

3. नियम 86 का संशोधन.—उक्त नियमों के नियम 86 में,—

(क) उप-नियम (1) में, “और जिला परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उप-नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम (1-क) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“(1-क) सम्बन्धित उपायुक्त यथाशक्य सम्भव परन्तु उप-नियम (1) के अधीन शपथ या राज्य निष्ठा का प्रतिज्ञान दिलाए जाने या किए जाने के सात दिनों के अपश्चात् अपनी अध्यक्षता में, सभी निर्वाचित सदस्यों की, उनमें से किसी एक को जिला परिषद् का अध्यक्ष और दूसरे किसी को उपाध्यक्ष चुनने के लिए बैठक बुलाएगा :

परन्तु यह कि राज्य सरकार, माधारण या विधेय आदेश द्वारा, इस उप-नियम के अधीन जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचन के परिणाम की घोषणा से एक सप्ताह के पश्चात् परन्तु एक महीने के अपश्चात् अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन बैठक करने की अनुमति प्रदान कर सकेगी :—

- (i) यदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण सात दिनों के भीतर बैठक बुलाई जानी सम्भव नहीं है ;
- (ii) यदि विधि और व्यवस्था की गम्भीर समस्याओं के कारण सात दिनों के भीतर बैठक बुलाना सम्भव या वांछनीय नहीं है ; और
- (iii) यदि विद्यमान पंचायतों की कालावधि के अवमान से 15 दिनों से अधिक अवधि से पूर्व निर्वाचन परिणाम घोषित कर दिए गए हैं।” ; और

(ग) उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा ; अर्थात् :—

“उप-नियम (1) के अधीन शपथ या निष्ठा के प्रतिज्ञान के प्रयोजनों के लिए बुलाई गई बैठक के लिए कोई गणपूर्ति अपेक्षित नहीं होगी। उप-नियम (1-क) के अधीन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के प्रयोजनों हेतु बैठकों के लिए गणपूर्ति कुल निर्वाचित सदस्यों के दो-तिहाई से होगी :

परन्तु यह कि यदि इस नियम के अधीन बुलाई गई प्रथम बैठक में गणपूर्ति के अभाव में, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन नहीं होता है, तो प्रथम बैठक की तारीख से दस दिन के भीतर द्वितीय बैठक बुलाई जा सकेगी और यदि फिर भी गणपूर्ति न होने पर द्वितीय बैठक स्थगित हो जाती है, तो तृतीय बैठक, द्वितीय बैठक की तारीख से दस दिन के भीतर बुलाई जा सकेगी। यदि तृतीय बैठक भी गणपूर्ति पूरी न होने पर स्थगित हो जाती है, तो तृतीय बैठक से दस दिन के भीतर चतुर्थ बैठक बुलाई जा सकेगी और अधिनियम की धारा 131 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन साथ-साथ कार्रवाई की जाएगी। चतुर्थ बैठक के लिए गणपूर्ति कुल निर्वाचित सदस्यों के आधे से होगी।” ।

प्ररूप 40 का संशोधन.—उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप 40 में,—

(क) शीर्षक “जिला परिषद्/पंचायत समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन” के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“पंचायत समिति/जिला परिषद् के सदस्यों के लिए शपथ या निष्ठा पर किया गया प्रतिज्ञान या पंचायत समिति/जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन” ; और

(ख) शब्द “और” के स्थान पर “या” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव ।

[Authoritative English text of this Department Notification No. PCH-HA (3)-1/94 dated 26th December, 2000 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.]

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 26th December, 2000

No. PCH-HA(1)12/2000.—Whereas the draft Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Amendment Rules, 2000 were published in the Rajpatra of Himachal Pradesh (Extra Ordinary) for inviting objections and suggestions *vide* Government Notification of even number on 19th December, 2000 under the provisions of section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994;

And whereas, the objections/suggestions received during the stipulated period have been considered by the State Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994), the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994, notified *vide* notification number PCH-HA(3)6/94, dated 7th February, 1995 and published in the Rajpatra (Extraordinary), Himachal Pradesh on 8th February, 1995, namely:—

1. *Short title.*—These rules may be called as the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Amendment Rules, 2000.

2. *Amendment of rule 85.*—In rule 85 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rule, 1994 (hereinafter called the “said rules”),—

(a) in sub-rule (1), the words “and for the election of Chairman and Vice-Chairman of Panchayat Samiti” shall be deleted;

(b) after sub-rule (1), the following sub-rule (1-A), shall be added, namely:—

“(1 A). As soon as possible but not later than seven days after oath or affirmation of allegiance under rule (1) is administered or made, the Deputy Commissioner concerned or any other officer authorised by him in this behalf except Block Development Officer shall call under his presidentship a meeting of all elected members to elect one of its members to be the Chairman and another member to be the Vice-Chairman of the Panchayat Samiti :

Provided that the State Government may, by general or special order, allow holding of meeting for the election of Chairman and Vice-Chairman under this sub-rule after one week but not later than one month from declaration of result of election of the elected members of the Panchayat Samiti under the following circumstances :—

(i) if it is not possible to convene meeting within seven days due to natural calamities ;

(ii) if it is not possible or desirable to hold meeting within seven days due to severe law and order problem ; and